अप्रैल में वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर

दोपहिया वाहन बिक्री में 28.4% की बढ़ोतरी

मांग में मजबूती से ऑटो सेक्टर को मिला सहारा

नई दिल्ली, 14 मई देश में वाहनों की मांग में पिछले साल सितंबर से जारी तेजी अप्रैल 2026 में भी बरकरार रही. इस दौरान घरेलू बाजार में यात्री वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई.

वाहन निर्माताओं के संगठन सीआईएएम द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सभी प्रमुख सेगमेंट में सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि देखने को मिली है. अप्रैल 2026 में देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया. यात्री वाहनों की बिक्री, जिनमें कारें, उपयोगी वाहन और वैन शामिल हैं, में स्थिर वृद्धि देखने को मिली. बाजार में मांग में सुधार का यह सिलसिला पिछले कई महीनों से जारी है.

तिपहिया वाहनों की बिक्री में इस महीने सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की गई. यह आंकड़ा 32.8 प्रतिशत बढ़कर 4,37,312 इकाई तक पहुंच गया. पिछले वर्ष इसी अवधि में यह बिक्री 3,28,847 इकाई थी. यह वृद्धि मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवहन की बढ़ती जरूरतों के कारण देखी गई. दोपहिया वाहनों के सेगमेंट में भी मजबूत उछाल दर्ज किया गया. कुल बिक्री 28.4 प्रतिशत बढ़कर 18,72,691 इकाई पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह 14,59,491 इकाई थी.

इस श्रेणी में मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों की बिक्री में सुधार देखने को मिला. विशेष रूप से स्कूटरों की बिक्री 26.2 प्रतिशत बढ़कर 6,91,993 इकाई तक पहुंच गई.

मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, और कुल बिक्री 11,35,442 इकाई रही.

> ऑटो सेक्टर में यह तेजी स्थिर आर्थिक स्थिति, बेहतर उपभोक्ता विश्वास और त्योहारों के बाद बनी मांग के कारण है. हालांकि वैश्विक स्तर पर कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, लेकिन घरेलू बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है. कुल मिलाकर, अप्रैल 2026 के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले महीनों में भी इस रफ्तार के जारी रहने की उम्मीद है.

एयरटेल का मुनाफा 39 प्रतिशत बढ़कर 7,245 करोड़ रुपये रहा

नयी दिल्ली, 14 मई देश की अग्रणी दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में समेकित आधार पर 7,245 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया, जो एक साल पहले की समान तिमाही के मुकाबले 38.7 प्रतिशत अधिक है.

कंपनी के निदेशक मंडल की बुधवार को हुई बैठक के बाद जारी वित्तीय परिणामों के अनुसार, तिमाही के दौरान उसका कुल राजस्व 15.7 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 55,383 करोड़ रुपये हो गया. उसका परिचालन लाभ 16.9 फीसदी बढ़कर 32,038 करोड़ रुपये रहा.

निदेशक मंडल ने पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर पर प्रति शेयर 24 रुपये के लाभांश की भी घोषणा की.

जीटीएल इंफ्रा का लाभ और 5जी में अवसर

ईबीआईटीडीए में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी

26,000 टॉवरों का व्यापक नेटवर्क मजबूत आधार

नई दिल्ली, 14 मई देश की टेलीकॉम आधारभूत संरचना कंपनी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने मार्च 2026 की तिमाही में अपने संचालन में मजबूती दिखाई है. कंपनी का ईबीआईटीडीए बढ़कर 64.84 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 49.22 करोड़ रुपये था. यानी इसमें लगभग 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

यह दर्शाता है कि कंपनी का मुख्य कारोबार पहले की तुलना में अधिक मजबूत और लाभदायक हो रहा है. वहीं, देश में 5जी नेटवर्क के तेजी से विस्तार से इसे आने वाले समय में और फायदा मिलने की संभावना है.

जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक टेलीकॉम टावर कंपनी है. यह मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को टावर और नेटवर्क संरचना उपलब्ध कराती है. कंपनी खुद मोबाइल सेवा प्रदान नहीं करती, बल्कि पूरे देश में टेलीकॉम कंपनियों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करती है. कंपनी का ईबीआईटीडीए यह दर्शाता है कि मुख्य कारोबार से कंपनी कितनी आमदनी कमा रही है, जिसमें ब्याज, कर और अन्य गैर-संचालन खर्च शामिल नहीं होते. मार्च 2026 तिमाही में कंपनी का ईबीआईटीडीए 64.84 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 49.22 करोड़ रुपये था. इस तरह इसमें 31.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई. साथ ही, कंपनी की प्रति शेयर आमदनी (ईपीएस) 0.19 रुपये से बढ़कर 0.91 रुपये हो गई. कंपनी के पास लगभग 26,000 टावर हैं, जो भारत के सभी 22 टेलीकॉम सर्किलों में फैले हुए हैं.

> अब भारत में 5जी तकनीक का तेजी से विस्तार हो रहा है. 5जी नेटवर्क के लिए अधिक टावर और मजबूत नेटवर्क की जरूरत होती है. इससे टावर कंपनियों की मांग बढ़ती है और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों के लिए अवसर बढ़ जाते हैं. 5जी के विस्तार से टावर साझा करने वाला मॉडल और बढ़ेगा. इससे कंपनी नए अनुबंध और बढ़ी हुई आमदनी प्राप्त कर सकती है.

मंदी की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली,14 मई दुनिया की बड़ी वित्तीय संस्थाओं और अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक आर्थिक मंदी को लेकर चेतावनी दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में वैश्विक मंदी की संभावना 35 से 40 फीसदी तक जताई गई है.

अमेरिका की आक्रामक टैरिफ नीति, कमजोर उपभोक्ता खर्च और ट्रेड वॉर को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत जरूर है, लेकिन वैश्विक सुस्ती का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है.

दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. जेपी मॉर्गन और मैकिंजी जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों ने 2026 में वैश्विक मंदी की आशंका जताई है. रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती की संभावना 35 से 40 फीसदी तक पहुंच गई है. इसके पीछे अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी, ट्रेड वॉर और कमजोर उपभोक्ता मांग को मुख्य कारण बताया जा रहा है.

मशहूर अर्थशास्त्री और मेरिल लिंच के पूर्व फोरकास्टर गैरी शिलिंग ने भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि 2026 के अंत तक अमेरिका मंदी की चपेट में आ सकता है. शिलिंग के मुताबिक हाउसिंग मार्केट में सुस्ती, कॉर्पोरेट निवेश में गिरावट और उपभोक्ताओं की कमजोर होती क्रय शक्ति चिंता का बड़ा कारण है. उन्होंने शेयर बाजार में बड़े करेक्शन की भी आशंका जताई है.

> अरबपति निवेशक लियोन कूपरमैन ने भी बाजार की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि शेयर बाजार का मूल्यांकन जरूरत से ज्यादा ऊंचा हो चुका है और कई आर्थिक जोखिम एक साथ बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक बाजारों में गिरावट आती है तो उसका असर दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी दिखाई देगा. भारत की बात करें तो घरेलू मांग और मजबूत बैंकिंग सिस्टम देश को कुछ हद तक सुरक्षा दे सकते हैं.

भारतीय शेयर बाजारों में आई तेजी

789 अंक चढ़ा सेंसेक्स

277 अंक की ऊंचाई निफ्टी में

मुंबई, 14 मई बैंकिंग, धातु और फार्मा सेक्टरों में लिवाली से घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को तेजी देखी गयी और प्रमुख सूचकांक एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त में बंद हुए.

बीएसई का सेंसेक्स 789.74 अंक (1.06 प्रतिशत) चढ़कर 75,398.72 अंक पर पहुंच गया. यह लगातार दूसरा दिन है जब बाजार में तेजी रही है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 277 अंक यानी 1.18 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,689.60 अंक पर बंद हुआ.

वृहत बाजार में निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.17 प्रतिशत चढ़ा जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक में 0.01 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी.

आईटी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों में लिवाली रही. निफ्टी आईटी सूचकांक 1.99 प्रतिशत गिर गया. धातु, फार्मा और स्वास्थ्य सेक्टरों के सूचकांक दो से तीन प्रतिशत तक ऊपर रहे. बैंकिंग, वित्त, रसायन, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद और मीडिया समूहों की कंपनियों में भी निवेशकों ने अच्छा पैसा लगाया.

सेंसेक्स में भारती एयरटेल का शेयर सबसे अधिक सवा पांच फीसदी से ज्यादा की बढ़त में रहा. कंपनी के अच्छे तिमाही परिणाम के बाद यह तेजी देखी गयी. इटरनल का शेयर सवा तीन प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक का ढाई फीसदी और अडानी पोर्ट्स का दो प्रतिशत से अधिक की बढ़त में रहा.

अडानी एयरपोर्ट्स के पास खुलेंगे होटल

मुंबई, 14 मई देश के हवाई अड्डा क्षेत्र में बड़ी साझेदारी देखने को मिली है. अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और ब्रिटेन की होटल कंपनी आईएचजी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, भारत के पांच प्रमुख शहरों में नए होटल विकसित किए जाएंगे. यह होटल उन शहरों में बनाए जाएंगे जहां अडानी समूह के एयरपोर्ट संचालित होते हैं. इस समझौते के तहत 1,500 नए कमरे विभिन्न ब्रांड्स के तहत जोड़े जाएंगे. इसमें जयपुर में 'किम्पटन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स' की शुरुआत भी शामिल है, जो भारत में इस ब्रांड का पहला प्रवेश होगा. इसके अलावा नवी मुंबई, मेंगलुरु तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में 'हॉलिडे इन' और 'हॉलिडे इन एक्सप्रेस' होटल भी विकसित किए जाएंगे.

सोना महंगा, चांदी में बड़ी गिरावट

चांदी में 5,800 की गिरावट, सोना 1,100 तक हुआ महंगा

नई दिल्ली, 14 मई सोने और चांदी की कीमतों में आज सर्राफा बाजार और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मिला-जुला रुख देखने को मिला. एक तरफ जहां सोने के दाम में तेजी दर्ज की गई, वहीं चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई. कस्टम ड्यूटी में बदलाव के बाद बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है.

एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी की कीमत करीब 5,800 तक गिर गई. 3 जुलाई डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 3,00,238 प्रति किलो पर बंद हुई थी, लेकिन आज यह गिरकर 2,94,450 तक पहुंच गई. सुबह के कारोबार में यह 2,98,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, जो लगातार दबाव को दर्शाता है. वहीं सोने की बात करें तो इसमें हल्की तेजी दर्ज की गई. 5 जून डिलीवरी वाला सोना कारोबार के दौरान 1,159 तक गिरने के बाद फिर से रिकवर हुआ और 480 की बढ़त के साथ 1,62,666 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा. सर्राफा बाजार में भी इसी तरह का रुझान देखने को मिला. 24 कैरेट सोना ?330 की तेजी के साथ 1,62,330 पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना 1,48,800 और 18 कैरेट सोना 1,21,750 पर ट्रेड करता दिखा.

ऊर्जा संकट में सरकार बनी ढाल, सामान्य रूप से हो रहे कार्य

वैश्विक युद्ध और होर्मुज संकट का असर आज पूरी दुनियामहसूस कर रही है। युद्ध की लपटें केवल सीमाओं तक सीमित नहीं हैं, उनका असर हर घर की रसोई, हर वाहन के पहिए और हर परिवार केबजट तक पहुंच चुका है।

कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें इतिहास के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगीं, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी और सरकारें अपने नागरिकों के गुस्से का सामना करने को मजबूर हो गईं। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच आज युद्ध के लगभग 11 सप्ताह बीतने पर भी भारत में जीवन की सामान्य गति बनी रही, करोड़ों परिवारों के चूल्हे जलते रहे, गाड़ियां चलती रहीं। यह अपने आप नहीं हुआ। इसके पीछे एक ऐसी नीति, ऐसी तैयारी और ऐसी संवेदनशील सोच थी जिसने वैश्विक तूफान के सामने भारत के नागरिकों को ढाल बनकर संरक्षण दिया। 28 फरवरी के बाद से वैश्विक स्तर परपेट्रोल-डीजल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। यूरोप और एशिया के कई देशों में पेट्रोल 30 से लेकर 35 प्रतिशत तकमहंगा हुआ, जबकि भारत में कोई बदलाव नहीं किया गया। हांगकांग में आज पेट्रोल सबसे महंगा है। वहाँ एक लीटर की कीमत लगभग295 रुपये पहुंच गई है, जो 28 फरवरी के बाद 25 प्रतिशत बढ़ी है।सिंगापुर में दाम 30 प्रतिशत बढ़कर करीब 240 रुपये प्रति लीटर होगया है। नीदरलैंड में पेट्रोल 225 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, जो28 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। युद्धग्रस्त इजराइल में पेट्रोल 30 प्रतिशतमहंगा होकर 185 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं भारत मेंअब भी पेट्रोल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर है। प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ का घाटा उठाना कोई साधारणबात नहीं है। अब तक लगभग 68,000 करोड़ का बोझ सरकार औरतेल कंपनियों ने अपने ऊपर लिया है। यह आंकड़ा उस संवेदनशीलसोच का प्रमाण है जिसमें मोदी सरकार ने पहले नागरिकों की चिंता की और बाद में अपने खजाने की। लेकिन साल 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आते हीस्थितियां बदलनी शुरू हुईं। पिछले वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो दूरदर्शी तैयारी की गई, वही आज देश की ढाल बनकर खड़ी है। तेलभंडार तैयार किए गए, एथनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाई गई, वैकल्पिक ईंधननेटवर्क विकसित हुआ और रिफाइनिंग क्षमता का विस्तार शुरू हुआ। वैकल्पिक ईंधन के माध्यम से एलपीजी की मांग को 70 से 75 हजारटन प्रति दिन कम किया गया। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकिपीएनजी, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल और बायोमास की वैकल्पिक अवसंरचना संकट से पहले से तैयार थी।

> जब दुनिया ऊर्जा संकट कीआग में झुलस रही थी, तब मोदी सरकार एक संरक्षक की तरह अपनेनागरिकों के साथ खड़ी रही। दुनिया भर में बढ़तीकीमतों का बोझ सीधे जनता पर डाल देना सबसे आसान रास्ता थाऔर कई देशों ने ऐसा ही किया, लेकिन भारत ने यह रास्ता नहीं चुना।मोदी सरकार ने स्वयं भारी आर्थिक दबाव सहा ताकि आम आदमी कीरसोई और रोजमर्रा की जिंदगी पर कम से कम असर पड़े। सरकार ने लगभग पेट्रोल पर 24 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 30 रुपये प्रतिलीटर का भार वहन किया।

समाचार विशेष

पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा फेरबदल

शोभनदेब चट्टोपाध्याय बने नेता प्रतिपक्ष

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद हर दिन बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नबान्न (सचिवालय) में कदम रखते ही कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं.

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में अपनी भूमिका तय कर ली है. अनुभवी नेता शोभनदेब मुखोपाधि को विपक्ष का नेता चुना गया है. उनके साथ असीमा पात्र और नयना बनर्जी को उप-नेता बनाया गया है, जबकि फिरहाद हकीम मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी संभालेंगे. 80 सदस्यों वाले विपक्ष के साथ शोभनदेब अब सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे.

अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में कटौती- मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कार्यभार संभालते ही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की. इसके तहत टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की जेड+ सुरक्षा वापस ले ली गई है. नबान्न से जारी निर्देश के अनुसार, अभिषेक को अब केवल वही सुरक्षा मिलेगी जो एक सामान्य सांसद को दी जाती है.

मुख्यमंत्री का तर्क है कि एक सांसद को इतनी भारी सुरक्षा और पुलिस बल की आवश्यकता नहीं है. इससे पहले उनके घर के सामने से भी पुलिस पहरा हटा दिया गया था.

पूर्व मंत्री सुजित बोस गिरफ्तार- नगर निकाय भर्ती घोटाले में घिरे पूर्व अग्निशमन मंत्री सुजित बोस की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सोमवार को करीब 10 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. ईडी का कहना है कि उनके बयानों में काफी विसंगतियां थीं. गिरफ्तारी से पहले उनके बेटे से भी पूछताछ की गई थी. सुजित बोस को मंगलवार सुबह अदालत में पेश किया जाएगा.

> **महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर**
>
> चुनावी वादे को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि अब पश्चिम बंगाल में महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु की तर्ज पर बंगाल में भी स्त्री शक्ति को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है. यह भाजपा के संकल्प पत्र का एक प्रमुख हिस्सा था, जिसे सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठकों के बाद लागू करने का निर्देश दिया है.

पश्चिमी यूपी में दलों ने बढ़ाई सक्रियता

2027 के रण की तैयारी, सम्मेलन और सभाओं से गरमाई राजनीति

सहारनपुर. वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. विभिन्न दलों ने अभी से संगठन मजबूत करने और चुनावी माहौल बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.

सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने देवबंद के जड़ौदा जट्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा आयोजित कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था. इसके बाद अब कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं.

कांग्रेस पार्टी 18 मई को गागलहेड़ी में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने जा रही है. पार्टी नेताओं के अनुसार इस सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव समेत कई वरिष्ठ नेता और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे.

> **भाजपा के शक्ति प्रदर्शन के बाद बढ़ी हलचल**
>
> देवबंद में हुए शक्ति प्रदर्शन के बाद विपक्षी दलों में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 की लड़ाई केवल चुनावी वर्ष में नहीं बल्कि उससे पहले संगठन को मजबूत करने और माहौल बनाने से तय होगी. इसी कारण आने वाले महीनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे, सम्मेलन और राजनीतिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती है.

तमिलनाडु की दोनों द्रविड़ पार्टियों की समस्या

चेन्नई. तमिलनाडु की दोनों द्रविड पार्टियों, जिन्होंने करीब 60 साल तक बारी बारी से राज्य में शासन किया उनकी हालत खराब है. छह दशक में पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों द्रविड पार्टियां एक साथ सत्ता से बाहर हो गईं और एक नई पार्टी का राज्य की राजनीति में उदय हुआ. फिल्म स्टार विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनी और छोटी पार्टियों के समर्थन से उसने सरकार बना लिया.

इस संकट का सबसे पहला असर अन्ना डीएमके पर पड़ा, जिसके दो टुकड़े हो गए हैं. 30 विधायकों का एक धड़े ने अलग नेता चुना है और 17 विधायकों ने पार्टी महासचिव ई पलानीसामी को नेता चुना है. स्पीकर को फैसला करना है कि असली पार्टी कौन सी है.

लेकिन ऐसा नहीं है कि एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके में सब कुछ ठीक है. अभी लग रहा है कि कोई परेशानी नहीं है लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि स्टालिन के लिए भी अपने बेटे उदयनिधि को विधायक दल का नेता चुनवाना आसान नहीं होगा. उनके साथ समस्या यह है कि खुद स्टालिन कोलाथुर सीट से चुनाव हार गए हैं. अगर वे जीते होते तो उनको नेता चुनने में किसी को समस्या नहीं आती. लेकिन उदयनिधि के नाम पर कई विधायकों को आपत्ति है. वे अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. तभी स्टालिन ने विधायक दल की बैठक टाल दी. कहा जा रहा है कि उदयनिधि के नाम पर सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

विशेष | **निशांत पर कुछ कहने से क्यों बच रहे जदयू प्रमुख**

नीतीश की चुप्पी के पीछे क्या है बड़ा गेम प्लान?

पटना. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मंगलवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे. जदयू के मंत्रियों की होने वाली जनसुनवाई की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान जब नीतीश कुमार से उनके बेटे निशांत के मंत्री बनने पर सवाल किया गया, तब वे हाथ जोड़ कर मुस्कुराते आगे बढ़ गये.

उन्होंने एक बार फिर जता दिया कि वे अपने पुत्र की राजनीति पर कुछ नहीं कहेंगे. वे नहीं चाहते थे कि निशांत राजनीति में आएं. निशांत की भी राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी. लेकिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में निशांत को राजनीति में आना पड़ा और मंत्री भी बनना पड़ा. अब जब निशांत ने मंत्री के रूप में नयी राजनीतिक पारी शुरू कर ही दी है तो उन्हें पार्टी के हर वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता का समर्थन प्राप्त है. उन्हें नीतीश कुमार का भी मौन समर्थन प्राप्त है. लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे प्रकरण पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.

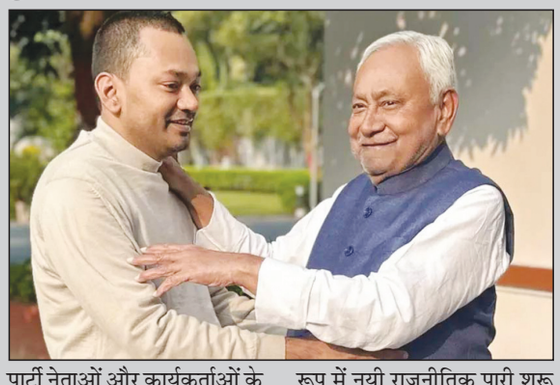

जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, निशांत के संबंध में किसी प्रश्न पर मौन रहना ही उचित समझते हैं. इसके दो कारण हैं. पहला यह कि वह कुछ बोलें और उस पर विवाद शुरू हो जाए, ये उन्हें मंजूर नहीं. तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगती. बेटे की राजनीति को लेकर वे अपनी तरफ से किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते. निशांत के राजनीति में आने के बाद विरोधी तो पहले से ही बोल रहे हैं.

> **नीतीश के मार्गदर्शन में ही काम करेगी नयी सरकार**
>
> ऐसा नहीं है नीतीश कुमार इस बात से अंजान हैं. उनके मार्गदर्शन में हरसंभव यही कोशिश होगी कि सम्राट सरकार सरकार ऐसी कोई गलती न करे. डील के मुताबिक नयी सरकार को नीतीश की लाइन पर ही चलना है. नीतीश सरकार की यूएसपी गुड गवर्नेंस रही है. सम्राट चौधरी भी इसी लाइन पर रहेंगे तो तेजस्वी के लिए शायद ही मौका मिले. सुशासन बनाम जंगलराज का मुद्दा आगे भी जीवित रहेगा.